

बिहार सरकार  
कला एवं संस्कृति विभाग

संकल्प

संख्या-4सं./प्र.2-04/2016 (खण्ड-2).....294/ पटना, दिनांक 13/8...../2026

**विषय:-** भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम ज्ञान भारतम मिशन के अन्तर्गत सर्वेक्षित पाण्डुलिपियों के डिजिटलीकरण और मेटाडेटा निर्माण योजना की स्वीकृति एवं इस पर कुल राशि ₹ 6,23,68,718/- (छः करोड़ तेईस लाख अड़सठ हजार सात सौ अठारह रुपये) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राज्यादेश।

भारत सरकार द्वारा भारत की समृद्ध ज्ञान परम्परा और बौद्धिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में फ्लैगशिप पहल के रूप में "ज्ञान भारतम मिशन" की घोषणा की गई है। इस मिशन के अन्तर्गत देश भर में उपलब्ध भारतीय ज्ञान परम्परा से जुड़ी पाण्डुलिपियों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण, डिजिटাইजेशन एवं अभिलेखीकरण किया जा रहा है, ताकि यह अमूल्य धरोहर शोधार्थियों/विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए सुलभ हो सके।

2- ज्ञान भारतम मिशन के प्रथम चरण में पाण्डुलिपियों के सर्वेक्षण हेतु दिनांक 16.03.2026 से राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वे प्रारम्भ हुआ है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या- GBM/42/2026-25 (E-78817), दिनांक-27.05.2026 के माध्यम से सूचित किया गया है कि राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण के दौरान चिह्नित पाण्डुलिपियों का डिजिटलीकरण और मेटाडेटा निर्माण किया जाना है। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा एजेन्सी का चयन किया गया है, जिसका दर ₹ 3.34/- (जी0एस0टी0 रहित) प्रति ईमेज निर्धारित किया गया है। इस क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित Specifications के अनुरूप अपने स्तर से एजेन्सी का चयन कर डिजिटलइजेशन का कार्य कराने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। इस कार्य में किये गये वास्तविक खर्च का ऊपर उल्लिखित दर की सीमा तक प्रतिपूर्ति डिजिटलीकरण कार्य के संतोषजनक निष्पादन के प्रमाण पत्र, वेन्डर के भुगतान का इनवॉइस एवं वेन्डर को किये गये भुगतान के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जायेगी। बिहार राज्य में राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वे के क्रम में अब तक आठ लाख से अधिक पाण्डुलिपियों को चिह्नित किया जा चुका है। पूरी योजना के दौरान लगभग दस लाख पाण्डुलिपियों में पृष्ठों की अनुमानित संख्या 1,58,24,804 है। भारत सरकार द्वारा चयनित एजेन्सी के दर के अनुसार डिजिटलीकरण का अनुमानित लागत ₹ 6,23,68,718/- (छः करोड़ तेईस लाख अड़सठ हजार सात सौ अठारह रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- इस योजना के लिए मांग संख्या 08 के अंतर्गत नया बजट शीर्ष खोलकर बजट उपबंध कराया जायेगा।

4- प्रस्ताव पर दिनांक 08.07.2026 को सम्पन्न बैठक में लोक वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

5- प्रस्ताव पर दिनांक-05.08.2026 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रणव कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 4सं./प्र०2-04/2016 (खंड-2)-294/

पटना, दिनांक 13/8/2026

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, वित्त विभाग, पुराना सचिवालय, पटना/ई०-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(प्रणव कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 4सं./प्र०2-04/2016 (खंड-2)-294/

पटना, दिनांक 13/8/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रणव कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 4सं./प्र०2-04/2016 (खंड-2)-294/

पटना, दिनांक 13/8/2026

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रणव कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— 4सं./प्र०2-04/2016 (खंड-2)-294/

पटना, दिनांक 13/8/2026

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रणव कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— 4सं./प्र०2-04/2016 (खंड-2)-294/

पटना, दिनांक 13/8/2026

प्रतिलिपि : सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित), कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/अपर निदेशक/सहायक संग्रहालयाध्यक्ष, पटना संग्रहालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(प्रणव कुमार)

सरकार के सचिव।